अति तत्काल

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी० एण्ड सी०

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 जून, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए मई, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में मई, 2020 माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)

अवर सचिव (पी. एंड सी.)

दूरभाष नं० 2338 1233

<u>प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-</u>

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पी.आई.बी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. ✓ उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के मई, 2020 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. **<u>प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) और एएनबी पैकेज:</u>**

आज की तारीख तक, 1,951 लाख मीट्रिक टन दालों के मासिक आबंटन के लिए, जो 3 माह के लिए 5.86 लाख मीट्रिक टन में से, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 5.42 लाख मीट्रिक टन भेजी गई जिसमें से उन्हें 4.81 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुई तथा 2.90 लाख मीट्रिक टन अंतिम लाभार्थियों को वितरित की गई।

आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत, प्रत्येक प्रवासी मजदूर परिवार को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत नहीं आते या जहाँ वे रहते है वहां के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का राशन कार्ड नहीं है को सरकारी बफर स्टॉक से 2 किग्रा साबूत चना की आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है। वितरण के लिए साबुत चना की मात्रा एनएफएसए के कवर किए गए परिवारों की संख्या का 10% अनुमानित है तथा जो लगभग 35,000 मीट्रिक टन साबुत चना है। 9 जून, 2020 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 0.33 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हो चुकी है तथा 1679 मीट्रिक टन लाभार्थी परिवारो को वितरित की जा चुकी है।

2. **<u>आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की समीक्षा:-</u>**

इस माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा के लिए तीन आईएमसी बैठकों का आयोजन किया गया। आईएमसी निर्णयों के आधार पर, 13 मई, 2020 को राजस्व विभाग को मसूर दाल पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 10% करने की सिफारिश की गई; उक्त विभाग द्वारा 3 जून 2020 को अधिसूचना जारी की गई।

3. **<u>दालों और प्याज का बफर स्टॉक</u>** –

(i) नेफेड ने यह सूचित किया कि मई, 2020 के दौरान पीएसएफ के तहत लगभग 56,000 मीट्रिक टन तूर खरीदा गया जिससे मई, 2020 तक खरीद कुल 1.77 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गई।

(ii) आईएमसी द्वारा पीएसएफ के तहत 1 लाख मीट्रिक टन प्याज की अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया और नेफेड से संपर्क किया किया गया। नेफेड द्वारा सूचना के अनुसार मई 2020 के अंत तक पीएसएफ के तहत लगभग 9189 मीट्रिक टन प्याज की अधिप्राप्ति की गई।

4. <u>भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)</u>:

(i) वर्तमान चल रही महामारी के दौरान गुणवत्ता पूर्ण पीपीई की सप्लाई को प्रोत्साहित करने के लिए, बीआईएस को उनके मापदण्डों में निम्नलिखित पीपीई के लिए इन-हाऊस जाँच सुविधा के लिए छूट दी गई है –

(क) आईएस 9473:2002 के अनुसार श्रेणी एफएफपी 2 के कणों से सुरक्षा के लिए फिल्टर हॉफ मास्क।

(ख) आई एस 16289:2014 के अनुसार सर्जिकल फेस मास्क

(ग) आई एस 5983:1980 के अनुसार आई प्रोटेक्टर

(ii) मास्क निर्माताओं की एक डायरेक्टरी तैयार की गई है और देश में मास्क निर्माताओं की क्षमताओं को निर्धारित करने का कार्य किया गया। बीआईएस संगठित क्षेत्र में 81 मास्क विनिर्माताओं से संपर्क स्थापित करने में सक्षम रहा। इन 81 मास्क विनिर्माताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया है कि उनका वर्तमान वार्षिक 2 प्लाई/ 3 प्लाई सर्जिकल मास्क उत्पादन क्षमता 295 करोड़ है। इसकी सूचना मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को समन्वित करने वाले अधिकार प्राप्त समूह को दी गई।

5. मुद्रास्फीति की वार्षिक दर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**सूचकांक**	**मुद्रास्फीति दर (%)**		
		अप्रैल, 2020 (अनन्तिम)	**मार्च, 2020 (अनन्तिम)**	**अप्रैल, 2019 (अंतिम)**
1	थोक मूल्य सूचकांक # **(वार्षिक)**	-^	1.00	3.24
2	थोक मूल्य सूचकांक # (**खाद्य वस्तुएं)**	2.55	4.91	6.44
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(गिक कामगारऔद्यो)**	5.45	5.50	8.33
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) **(संयुक्त)***	-^	5.84	2.86
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	-^	8.76	0.30

सीरीज 2012=100 # नया आधार वर्ष 2011-12=100 ^- कोविड 19 के कारण अप्रैल 2020 के लिए उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक - I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य अप्रैल, 2020 की तुलना में मई, 2020 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है:-

आवश्यक वस्तुओं का अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य (रु/किग्रा)

क्रम संख्या	वस्तु	मई, 2020 (अद्यतन)	अप्रैल, 2020 (विगत माह)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	34	34	0
2	गेहूं	29	29	0
3	आटा	31	31	0
4	चना दाल	68	69	-1
5	तूर दाल	95	95	0
6	उड़द दाल	104	104	0
7	मूंग दाल	111	109	2
8	मसूर दाल	76	73	3
9	चीनी	40	40	0
10	दूध (प्रति लीटर)	47	46	1
11	मूंगफली का तेल	147	144	3
12	सरसों का तेल	118	118	0
13	वनस्पति	91	90	1
14	सोया तेल	101	101	0
15	सूरजमुखी का तेल	111	110	1
16	पाम ऑयल	88	89	-1
17	गुड़	48	47	1
18	खुली चाय	218	219	-1
19	पैकबंद नमक	16	16	0
20	आलू	26	26	0
21	प्याज़	22	28	-6
22	टमाटर	20	22	-2

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण की गई महत्वपूर्म नीतिगत मामले:

शून्य

2. सीओएस निर्णयों का अनुपालन: - **ई-समीक्षा पोर्टल में अपडेट किया गया**

3. तीन माह से अधिक समय के लिए लंबित "अभियोजन की स्वीकृति" के मामलों की संख्या: -

शून्य

4. मामलों का विवरण जिसमें व्यापार नियमों के अंतरण से प्रस्थान या सरकार की स्थापित नीति हो:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यन्वयन की स्थिति: -

कुल फाईल संख्या	कुल ई-फाईल संख्या
96	81

6. लोक शिकायतों की संख्या:

मई 2020 माह के दौरान निपटाए गए लोक शिकायतों की संख्या	मई 2020 के अंत तक लंबित लोकशिकायतों की संख्या
786	642

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में दर्ज शिकायतों की स्थिति:

मई, 2020 माह के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कुल दर्ज डॉकेट्स	मई 2020 में निपटाए गए कुल डॉकेट
34528	642

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अधिशासन

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 114 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।